कमिश्नर, कृषि आय कर

बनाम

एम. एन. धोनी

मई 18, 2007

(डॉ. अरिजित पासायत, पी.के. बालासुब्रमण्यम और डी.के. जैन, जे.जे.)

केरल कृषि आयकर अधिनियम 1952:

धारा 60: उच्च न्यायालय को निर्देश - इस संदर्भ में केवल कानून के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जहां किसी मुद्दे का निर्धारण साक्ष्य या सामग्री के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनों के उपयोग के बिना बुनियादी तथ्यों का पता चलता है, तो यह मुद्दा केवल तथ्य का प्रश्न उठाता है। यदि कानून का कोई प्रश्न शामिल नही है तो मामलें को नए सिर से विचार के लिए न्यायालय में भेजा गया।

केरल कृषि आयकर अधिनियम 1952 के तहत कर निर्धारण अधिकारी की राय में कर निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए विवरण सही और पूर्ण नहीं थे और उन्होंने कर योग्य आय में 60.79 एकड़ से कॉफी की आय को शामिल किया। उपायुक्त (अपील) ने मूल्यांकन अधिकारी के निष्कर्षो की पुष्टि की। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अपीलों में, केरल

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने उक्त 60.79 एकड़ भूमि से आय के अनुमान की पुष्टि की। अधिनियम की धारा 60 के संदर्भ के लिए एक आवेदन पर, न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय को इस सवाल के लिए संदर्भित किया गया कि क्या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष 60.79 एकड भूमि से आय निर्धारिती के खातों में शामिल नही थी, किसी भी द्वारा समर्पित था।

सामग्री या साक्ष्य। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण का आदेश सही नहीं था और निर्धारिती के पक्ष में प्रश्न का निर्णय किया। इससे नाराज राजस्व विभाग ने तत्काल अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, बताया गया 1.1 एक संदर्भ में तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नही है, जब तक कि निष्कर्ष बिना किसी कारण या आधार के न हो। अभिलेख पर सामग्री के प्रतिकूल और/या विपरीत। सिर्फ इसलिए कि अलग तथ्यों पर दृष्टिकोण तैयार करने के लिए उपलब्ध हो सकता है, जो अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है। तत्काल मामले में, तथ्यों के निष्कर्ष मूल्यांकन प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी संकेत नहीं दिया है कि उसने निर्धारण

प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्षों को अस्थिर क्यों माना। [पैरा 12 और 15] [261-ए-बी; ई-एफ]

1.2. संदर्भ के मामलों में, केवल कानून के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। कहाँ? किसी मुद्दे का निर्धारण साक्ष्य या सामग्री के मूल्यांकन पर निर्भर करता है जिसके परिणामस्वरूप कानून के उपयोग के बिना बुनियादी तथ्यों का पता लगाया जाता है, यह मुद्दा केवल तथ्य का सवाल उठाता है। कुछ तथ्यों का हस्तक्षेप भी तथ्य का सवाल है। तथ्यों की सराहना पर आधारित निष्कर्ष कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देता है। यदि न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य को अनुचित रूप से अस्वीकार करने के बाद तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है, तो कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है। कहाँ का न्यायाधिकरण आंशिक रूप से प्रासंगिक और आंशिक रूप से अप्रासंगिक सामग्री पर कार्य करता है, कानून का एक सवाल उत्पन्न होता है क्योंकि यह कहना असंभव है कि न्यायाधिकरण का विनिश्चय निष्कर्ष पर पहुंचने में उसके द्वारा उपयोग की गई अप्रासंगिक सामग्री से किस हद तक प्रभावित हुआ था। तथ्य का प्रश्न कानून का प्रश्न बन जाता है यदि निष्कर्ष या तो बिना किसी सबूत या सामग्री के होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा सीधे या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर संदर्भ दिए जाने के बाद भी, यह उच्च

न्यायालय का विवेक है कि वह संदर्भ का जवाब न दे यदि कानून का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। [पैरा 13,14 और 15] [261-सी-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 2716

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.2004 से, जो कि 1999 के आई. टी. आर. सं. 143 और 144 में पारित किया गया।

अपीलार्थी के लिए जी. प्रकाश, बीना प्रकाश और रमेश बाबू एम. आर.।

उत्तरदाता की ओर से सी. एन. श्री कुमार।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। केरल कृषि आयकर अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत 259 के पक्ष में किए गए संदर्भ का जवाब देते हुए केरल उच्च न्यायालय प्रतिवादी (इसके बाद "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित)।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

4. मूल्यांकन वर्षों 1982-83 और 1983-84 के लिए, एम/एस। ई. के. विजयन और अन्य, कोझिकोड अधिनियम के तहत एक निर्धारिती था। श्री एम. एन. मोनी निर्धारिती की संपदाओं का निष्पादक। निर्धारिती के पास "वुडलैंड एस्टेट" नामक एक संपत्ति थी। कॉफी से प्राप्त कृषि आय, काली मिर्च, सुपारी, नारियल, इलायची और कोको। मूल्यांकन वर्षों के लिए अर्थात 1982-83 और 1983-84 निर्धारिती ने कृषि आय का खुलासा करते हुए विवरणी दाखिल की रुपये. 1,22,520/- और रुपये. 2,88,996/- क्रमशः। मूल्यांकन अधिकारी का था। यह विचार कि दाखिल किए गए विवरणी सही और पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते हैं क्योंकि निर्धारिती ने 1982-83 के दौरान कॉफी से होने वाली आय का खुलासा नहीं किया था। नारंगी, सुपारी, नारियल, इलायची, और कोको और कई से प्रकट अस्वीकार्य खर्चों को कटौती के रूप में दावा किया गया था। नोटिस जारी किए गए हैं। 2.3.1987 और 17.10.1987 सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन करने का प्रस्ताव। निर्धारिती ने नोटिसों पर अपना जवाब दाखिल किया। दाखिल आपत्तियों पर विचार करने के बाद, कृषि आयकर के निरीक्षण सहायक आयुक्त ने दो मूल्यांकन वर्षों के लिए क्रमशः रु. 7,97,380/- और रु. 5,06,641/- की आय निर्धारित करने वाले आकलन को पूरा किया। यह ध्यान दिया गया कि नए पंजीकृत क्षेत्र के 60.79 एकड़ के संबंध में ई. बी. 2 रजिस्टर नहीं था। उत्पादित किया। उक्त क्षेत्र के उत्पादन विवरण का भी खुलासा नहीं किया गया था। तदनुसार, 60.79 एकड़ से कॉफी की आय

का अनुमान लगाया गया था और कर योग्य आय में शामिल किया गया था। निर्धारिती द्वारा उपायुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जाती थी, जिन्होंने नए पंजीकृत क्षेत्र के 60.79 एकड़ और उससे होने वाली आय से संबंधित मुद्दे पर निर्धारण अधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि की। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि खेती के खर्च की अनुमति 2,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से दी जानी चाहिए। निर्धारिती ने वरीयता दी। केरल कृषि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, अतिरिक्त पीठ, कोझिकोड (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष दूसरी अपील। न्यायाधिकरण ने पाया कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत खाते केवल 218 एकड़ भूमि के संबंध में थे और 1 एकड़ भूमि से संबंधित गतिविधियों का खुलासा नहीं किया गया था। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने उपरोक्त से आय के अनुमान की पुष्टि की 60.79 एकड़ जमीन।

5. अधिनियम की धारा 60 के संदर्भ के लिए एक आवेदन था दाखिल किया। इसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। मूल याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थीं, जिसने 1 अप्रैल, 1996 के आदेश द्वारा न्यायाधिकरण को निर्धारिती द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक को संदर्भित करने और प्रश्न 260 को संदर्भित करने का निर्देश दिया था। तथ्यों के बयान के साथः

6. तदनुसार, संदर्भ बनाया गया था जिसे निपटाया गया था विवादित आदेश।

7. जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया था वह इस प्रकार हैः

> "चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, निष्कर्ष है न्यायाधिकरण की आय जो 60.79 एकड़ अपंजीकृत कॉफी से होती है, किसी द्वारा समर्थित क्षेत्र निर्धारिती के खातों में शामिल नहीं है। सामग्री या सबूत?"

8. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण सही नहीं था और प्रश्न का निर्णय निर्धारिती के पक्ष में किया जाना था।

9. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मूल प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने तथ्यात्मक स्थिति पर विस्तार से विचार किया और इस तथ्य के निष्कर्ष दर्ज किए कि 60.79 एकड़ भूमि आय के संबंध में खुलासा नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने चर्चा किए बिना तथ्यात्मक स्थिति, एक संक्षिप्त तरीके से, अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को अलग करती है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. इसके विपरीत, निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिया है और इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. हम पाते हैं कि विवाद का संक्षिप्त संदर्भ देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ संदर्भ का निपटारा कियाः

> "निर्धारिती का तर्क था कि जहाँ तक उनका संबंध है, उन्होंने संपत्ति से पूरी कृषि आय वापस कर दी है। इसके अलावा, यह निवेदन किया गया था कि कॉफी के संबंध में, वे नहीं बेच सकते हैं।
>
> तथ्य के उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार, निर्धारिती का तर्क है कि अधिकारियों का निष्कर्ष सही नहीं है। ट्रिब्यूनल, इसके बाद मामले पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्धारिती ने 60.79 एकड़ से वापसी नहीं दिखाई गई। हमारे अनुसार, यह दृष्टिकोण है पियर्स लेस्ली, विभाग के लिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि पूरी आय वापस नहीं की गई है।"

12. उच्च न्यायालय द्वारा आदेशों को बाधित करने का कोई कारण नहीं था निर्धारण प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरणों का निर्णय स्पष्ट है।

उक्त अधिकारियों द्वारा तथ्यों के निष्कर्ष दर्ज किए गए थे। वहाँ एक संदर्भ में तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक कि निष्कर्ष न हों बिना किसी कारण या आधार के, विकृत और/या रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत। केवल इसलिए कि तथ्यों पर अलग-अलग दृष्टिकोण तैयार करने के लिए उपलब्ध हो सकता है, यह अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

13. संदर्भ के मामलों में, केवल कानून के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जहाँ किसी मुद्दे का निर्धारण उसकी व्याख्या पर निर्भर करता है। साक्ष्य या सामग्री जिसके परिणामस्वरूप कानून के उपयोग के बिना बुनियादी तथ्यों का पता चलता है, यह मुद्दा केवल तथ्य का सवाल उठाता है। कुछ तथ्यों से निष्कर्ष निकालना भी तथ्य का सवाल है। प्रशंसा पर आधारित निष्कर्ष तथ्य कानून के किसी भी सवाल को जन्म नहीं देते हैं। यदि न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य को अनुचित रूप से अस्वीकार करने के बाद तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यह कानून का सवाल है। उठती है। जहां न्यायाधिकरण आंशिक रूप से प्रासंगिक और आंशिक रूप से अप्रासंगिक सामग्री पर कार्य करता है, कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है क्योंकि यह कहना असंभव है कि न्यायाधिकरण का दिमाग निष्कर्ष पर

पहुंचने में उसके द्वारा उपयोग की गई अप्रासंगिक सामग्री से किस हद तक प्रभावित हुआ था।

14. तथ्य का प्रश्न कानून का प्रश्न बन जाता है यदि निष्कर्ष या तो है बिना किसी सबूत या सामग्री के।

15. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने यह भी संकेत नहीं दिया है कि क्यों इसने निर्धारण प्राधिकरण और अपीलीय के निष्कर्षों पर विचार किया अधिकार अस्थिर होना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर निर्देश दिए जाने के बाद भी यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह संदर्भ का जवाब न दे यदि कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है।

16. इसलिए, गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम निर्धारित करते हैं उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दें और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उसे भेज दें। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई हर्जा खर्चा नहीं।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आँचल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।